रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022024-252084
CG-DL-E-15022024-252084

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 652] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 14, 2024/माघ 25, 1945
No. 652] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 14, 2024/MAGHA 25, 1945

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2024

का.आ. 688(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा किया जाना अपेक्षित है कि बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक की सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 32 के अधीन आती हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाये;

और, केन्द्रीय सरकार ने उक्त उद्योग को अंतिम बार उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2759(अ), तारीख 23 जून, 2023 द्वारा, तारीख 19 अगस्त, 2023 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार छह मास की अवधि के लिए किया जाना अपेक्षित है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उद्योग की सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तारीख 19 फ़रवरी, 2024 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं. एस-11017/04/2024-आई.आर.(पी.एल.)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2024.

S.O. 688(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the Services in the Bank Note Paper Mill India Private Limited, Mysore, Karnataka, which is covered under item 32 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 19th August, 2023, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 2759(E), dated the 23rd June, 2023;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 19th February, 2024.

[No. S-11017/04/2024-IR (PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA